आवेदक



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2015/माघ 21, 1936

No. 45]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2015/MAGHA 21, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अधिसूचना

मुम्बई, 4 फरवरी, 2015

सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, कांडला पत्तन न्यास के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण मामला सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास

कोरमः

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यम, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जनवरी 2015 के दूसरे दिन पारित)

यह मामला कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से सम्बंधित है।

- 2. केपीटी का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी दिनांक 18 जनवरी 2011, जिसे 22 फरवरी 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च 2013 तक निर्धारित करता है। यह प्राधिकरण केपीटी के दरमान की वैधता कई बार विस्तारित कर चुका है; पिछला विस्तार आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2014 द्वारा 31 दिसम्बर 2014 तक था।
- 3.1. केपीटी ने पहले अपने प्रस्ताव दिनांक 3 जनवरी 2013 द्वारा अपने दरमान के संशोधन के लिए एक प्रस्ताव दाखिल किया था जिसे जनवरी 2013 में प्रशुल्क मामले के रूप में पंजीकृत किया गया था और प्रासंगिक अंशधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इस प्राधि करण ने अपने आदेश सं टीएएमपी/73/2012-केपीटी दिनांक 4 जुलाई 2014 द्वारा केपीटी से संशोधित प्रस्ताव की मांग करते हुए मामले को बन्द करने का निर्णय लिया था और केपीटी को 2013-14 प्रोद्भृतों के आधार पर उसके दरमान के सामान्य संशोधन के लिए नया प्रस्ताव 31 अगस्त 2014 तक दाखिल करने की सलाह दी गई थी जिसे नया मामला माना जाना था।
- 3.2. केपीटी ने अपना संशोधित प्रस्ताव दिनांक 2 सितम्बर 2014 दाखिल किया था जिसपर उनकी टिप्पणियों के लिए प्रासंगिक अंशधारकों के साथ विचार–विमर्श किया गया था। इस प्रस्ताव की आंतरिक रूप में संवीक्षा की जा रही है। परामर्श प्रक्रिया के रूप में संयुक्त सुनवाई भी आयोजित की जाएगी।

724 GI/2015 (1)

- 4.1. इसी बीच, केओपीटी के मौजूदा दरमान की विस्तारित वैधता 31 दिसम्बर 2014 को समाप्त हो चुकी है। केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 24 दिसम्बर 2014 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा दरों को संशोधित किए जाने तक मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करने का अनुरोध किया था।
- 4.2. केपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के मद्देनजर और उपर्युक्त पैरा 3.2 में यथा दिए गए संशोधित प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए भी, इस प्राधिकरण के अंतिम विचार के लिए मामला तैयार करने में समय लगेगा। इसलिए, यह प्राधिकरण केपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता इसकी समाप्ति की तारीख से 31 मार्च 2015 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।
- 4.3. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल 2013 के बाद प्रकट होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णत: समायोजित किया जाएगा।

टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त) कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./143/2014 (289)]

TARIFFAUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th February, 2015

No. TAMP/61/2009-KPT.— In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Traiff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFFAUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No. TAMP/61/2009-KPT

The Kandla Port Trust --- Applicant

OUORUM

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 2nd day of January 2015)

This order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Kandla Port Trust (KPT)`

- 2. The existing Scale of Rates (SOR) of the KPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/61/2009-KPT dates 18 January 2011 which was notified in the Gazette of India on 22 February 2011. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2013. This Authority has extended the validity of SOR of KPT on couple of occasions; the last extension being till 31 December 2014 vide Order dated 30 September 2014.
- 3.1. The KPT had earlier filed a proposal for revision of its SOR Vide its proposal dated 3 January 2013 which was registered as tariff case in January 2013 and taken on consultation with relevant stakeholders. This Authority, vide its Order No. TAMP/73/2012-KPT dated 4 July 2014, had decided to close the case for want of revised proposal from the KPT and had also advised the KPT to file fresh proposal for general revision of its SOR based on 2013-14 actuals latest by 31 August 2014 which was to be treated afresh.
- 3.2. The KPT has filed its revised proposal dated 2 September 2014 which was taken on consultation with relevant stakeholders for their comments. The proposal is being intennally scrutinized. Joint hearing as part of the consultation process will also have to be set up.
- 4.1. In the meantime, the extended validity of the existing SOR of KPT expired on 31 December 2014. The KPT vide its letter dated 24 December 2014 has requested this Authority to extend the validity of the existing SOR till the rates are revised by this Authority.

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

4.2. In view of the request made by KPT and also considering the present status of the revised proposal as brought out is para 3.2. above, it will take time for the case to mature for final consideration of this Authority, This Authority therefore, extends the validity of the existing SOR of KPT from the date of its expiry till 31 March 2015 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

4.3. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/2014(289)]